दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो।
– अज्ञात

सुधार की गति बेहद धीमी

आज भी ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषणरोधी उपाय नहीं किए गए हैं। प्रदूषण कम करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी गंभीरता को समझना होगा, फिर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उससे निपटने के उपाय लागू करने होंगे।

अनुज शर्मा।

प्रदूषण को लेकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आगाह किए जाने के बावजूद इस क्षेत्र में सुधार की गति बेहद धीमी है। अब एक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने भारत में इसकी भयावहता की ओर ध्यान खींचा है। आईक्यूएयर एयर विजुअल और ग्रीनपीस के नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 10 शहरों में से सात भारत में हैं, जिनमें पांच तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही मौजूद हैं। वर्ष 2018 के दौरान प्रदूषण स्तर के मामले में गुरुग्राम पूरी दुनिया में टॉप पर है।

हालांकि पिछले साल की तुलना में उसका स्कोर कुछ बेहतर हुआ है। इस स्टडी में प्रदूषण मापने के लिए पीएम 2. 5 यानी ढाई माइक्रॉन (1 माइक्रॉन = 1 मिलीमीटर का सौवां हिस्सा) के आकार वाले कण को आधार बनाया गया। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की थी, जिनमें 14 भारत के थे। इधर कुछ सालों से सरकार पर्यावरण के मुद्दे को अपने अजेंडे में सबसे ऊपर रखने का दावा करने लगी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हर तरफ से दबाव पड़ता है तो सरकार आनन–फानन कुछ कदम उठा लेती है लेकिन फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है।

विकास के नाम पर सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को धुआं फैलाने की खुली छूट दे रखी है। हरियाणा के अरावली क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करते हुए 119 साल पुराना कानून बदल डाला। पीएलपीए (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900) में संशोधन के जरिए उसने अरावली और शिवालिक पहाड़ियों की 29,682 हेक्टेयर संरक्षित भूमि को विकास कार्यों के लिए खोल दिया। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन पर रोक लगा दी है।

कई और राज्यों ने भी पर्यावरण के नियमों को धता बताते हुए औद्योगिक इकाइयों, बिल्डरों और खनन माफिया को मदद पहुंचाई है। आईआईटी कानपुर की एक स्टडी के अनुसार प्रदूषण के लिए औद्योगिक इकाइयों और पराली जलाने जैसी सामयिक वजहों के अलावा गाड़ियों की बढ़ती संख्या, छोटे उद्योगों का डीजल जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भर होना और निर्माण कार्यों व टूटी सड़कों की वजह से हवा में धूल का उड़ना भी जिम्मेदार है। आज भी ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषणरोधी उपाय नहीं किए गए हैं।

कुछ शहरों में पेट्रोल–डीजल की जगह गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है लेकिन इसके अपेक्षित नतीजे अभी आने बाकी हैं।

महानगरों में सीएनजी पंपों पर लंबी–लंबी लाइनें लगी रहती हैं और अदालत के आदेशों के बावजूद पुरानी डीजल गाड़ियां सड़कों पर धुआं छोड़ती रहती हैं। प्रदूषण कम करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी गंभीरता को समझना होगा, फिर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उससे निपटने के उपाय लागू करने होंगे। पड़ोस में चीन ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते?

लोक का नियम

डॉ. अर्चिका दीदी।

धर्म-दर्शन

अब आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि यज्ञ कहते हैं त्याग को। 'यज्ञ' का त्याग नहीं करना चाहिए– इसका साफ–सा मतलब है कि 'त्याग' का त्याग नहीं करना चाहिए और जो यह करता है, वह ईश्वर को त्यागता है। आध्यात्म–दर्शन में 'अंतर्मन की यात्रा' को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। आप बहते हैं अंदर ही अंदर, सुख–शांति और समृद्धि की तलाश में। यहां समृद्धि को भौतिकता से न तौलें। अपने अंतःस्थल तक आप पहुंचते हैं। अपने सत्य को पाते हैं। अपने शिव, यानी कैलाशपति को आप पाते हैं। अपनी सुंदरता को आप पाते हैं। यानी कैलाश–यात्रा एक श्रेष्ठतम कर्म है। अब देखिए कि इस लोक का नियम है– ऊपर से नीचे की ओर आना। उदाहरण, पानी का प्रवाह देखें।

संपादकीय

उलट राय रखने वालों से

यह वाकई आश्वस्त करने वाली सूचना है कि इस गरमागरमी वाले माहौल में भी भारत के आधे से ज्यादा लोग अपने विरोधी विचारों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने से उलट राय रखने वालों से संवाद बनाए रखना आवश्यक मानते हैं। बीबीसी क्रॉसिंग डिवाइड्स ग्लोबल सर्वे के एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि 55 प्रतिशत भारतीय राजनीति, जलवायु परिवर्तन, आव्रजन और नारीवाद जैसे मुद्दों पर विरोधी विचार वाले लोगों के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार बातचीत करते हैं।

जहां तक राजनीति का प्रश्न है तो 42 प्रतिशत शहरी भारतीयों का कहना है कि वे विपरीत विचार वालों के साथ भी देश की सियासत पर चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं। ऐसे उदार नजरिए के लिहाज से इस सर्वेक्षण की सूची में भारत का मुकाम चौथा है। इस मामले में तुर्की (61 प्रतिशत) पहले स्थान पर है। उसके बाद मेक्सिको (45 फीसदी) और साउथ अफ्रीका (43 पर्सेंट) का स्थान है। सबसे नीचे जापान (7 फीसदी), दक्षिण कोरिया (27 फीसदी) और इटली (28 फीसदी) हैं।

यह सर्वेक्षण 27 देशों के लोगों के बीच किया गया। इसके अनुसार ज्यादातर भारतीय मानने लगे हैं कि सोशल मीडिया अब विचार–विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। लगभग 70 फीसदी शहरी भारतीयों का मानना है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ऐसे लोगों को आवाज दे रहे हैं जो आमतौर पर बहसों और सामाजिक विमर्श में हिस्सा नहीं लेते। इस सर्वेक्षण की अपनी सीमाएं हो सकती हैं लेकिन इससे भारतीय समाज की एक झलक तो मिलती ही है। इधर कुछ समय से समाज में एक विचित्र किस्म का विभाजन देखा जाने लगा है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी इंटरनेट के प्रयोग को मौलिक आजादी माना है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे देश में इंटरनेट पर रोक एक रुटीन की सी शक्ल ले बैठी है।

अधिकार का ही एक रूप

नवीन जोशी।

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार का ही एक रूप करार दिया है। शुक्रवार को यह अहम फैसला देते हुए उसने जम्मू–कश्मीर प्रशासन को इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी प्रतिबंध आदेशों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 144 सीआरपीसी (निषेधाज्ञा) का इस्तेमाल अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता। भविष्य में अगर कहीं धारा 144 लगाई जाती है तो सात दिनों के अंदर उसका रिव्यू जरूर होना चाहिए। लोगों को अधिकार होगा कि वे इसे कोर्ट में चुनौती दें।

बीते साल सितंबर में केरल हाई कोर्ट ने भी इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार बताया था। दुनिया भर में इंटरनेट को इसी रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी इंटरनेट के प्रयोग को मौलिक आजादी माना है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे देश में इंटरनेट पर रोक एक रुटीन की सी शक्ल ले बैठी है। जहां भी सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन होता है, प्रशासन झट इंटरनेट बंद करवा देता है। यह दलील देते हुए कि अफवाहों पर

नियंत्रण के लिए ऐसा करना जरूरी है। इंटरनेट पर बैन के मामले में भारत दुनिया में अव्वल हो गया है।

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस समेत दो थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2012 से लेकर बीते दिसंबर के मध्य तक सरकार ने 367 बार इंटरनेट बंद किया। 2018 में दुनिया भर में होने वाले कुल इंटरनेट शटडाउन में से 67 फीसदी भारत में हुए। इसके सबसे ज्यादा मामले कश्मीर में रहे– कुल 367 शटडाउन में से 180 सिर्फ कश्मीर में। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से 2017 के बीच इंटरनेट बंद होने से 3 अरब डॉलर (तकरीबन 21 हजार करोड़ रुपये) का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन को इंटरनेट बंद करने की ऐसी आदत हो गई है कि गुजरात में राजस्व लेखपाल की परीक्षा के दौरान नकल रोकने के नाम पर सुबह नौ बजे से एक बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एक जनतांत्रिक देश के लिए यह नितांत अशोभनीय है। हमें समझना होगा कि समय के साथ नई–नई तकनीकें जीवन में शामिल होती हैं और वे हमारी बुनियादी आवश्यकता बनती जाती हैं।

इंटरनेट सिर्फ सूचना या मनोरंजन का माध्यम भर नहीं है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान और कारोबार का एक बड़ा जरिया भी है। और जो चीज हमारे गरिमापूर्ण जीवन के लिए इतनी जरूरी है, उसका अबाधित इस्तेमाल निश्चय ही हमारा मूल अधिकार होना चाहिए, जिस पर प्रतिबंध अत्यंत आपात स्थितियों में ही लगाया जा सके। इसी तरह धारा 144 का प्रयोग भी असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बार–बार इस्तेमाल से जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। आशा है, सरकार कोर्ट के संदेश को उसके निहितार्थों के साथ ग्रहण करेगी।

अष्टयोग-4924

	2	5	6			3
2	26	4	40		38	
4	2			5	1	
5	34	3	37	6	30	1
	1	7			5	2
	33		24	1	27	6
7	6		4	2	3	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4923 का हल

4	3	7	1	6	2	5
3	29	6	37	2	31	1
1	2	3	7	5	6	4
5	30	1	30	4	31	6
7	6	5	4	1	3	2
2	33	4	31	3	30	7
6	1	2	5	7	4	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग — रिश्तों का फैलाव

प्रणव प्रियदर्शी। हंसी जोर की आई मुझे, उसके बाद समझ आया कि जाना–माना नाम होने से रिश्तों का फैलाव तो बहुत होता है, लेकिन इसकी गुंजाइश भी बढ़ जाती है कि 'दोस्ती' की नकाब लगाए इन सारे रिश्तों के पीछे अलग–अलग तरह के रिश्ते पल रहे हों। ऐसे हर रिश्ते के पीछे पलते असली रिश्ते का ठीक–ठीक हिसाब लगाना और सारे ब्यौरों सहित उसे याद रखना कितना झंझट वाला काम होता होगा। उसमें जरा सा चूके तो किसी शत्रु को मित्र समझ लेने की ऐसी गलती हो सकती है, जिसका खामियाजा जीवन के किसी नाजुक मोड़ पर हादसे की शक्ल में भुगतना पड़ सकता है। इससे भी गंभीर संभावना यह है कि किसी सच्चे मित्र को शत्रु समझने की गुस्ताखी हो जाए। शत्रु को मित्र समझने से तो सिर्फ ऐसा नुकसान होगा जिसे हम खुद झेल सकते हैं, पर मित्र को मन ही मन अमित्र समझने लगे और उसे इसका आभास हो गया तो जो चोट उसे पहुंचेगी उससे निस्तार का भी क्या कोई उपाय हो सकता है!